अर्जुन प्रसाद

बनाम

शांतिलाल शंकरलाल शाह एवं अन्य

(एवं संबद्ध अपील)

(के.सी. दास गुप्ता तथा रघुबर दयाल, न्यायमूर्तिगण)

कंपनी—क्या बैठक में "व्यक्तिगत रूप से" उपस्थित हो सकती है—लेनदारों की बैठक —लेनदार कंपनी का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त व्यक्ति—कंपनी की ओर से मतदान करने वाला व्यक्ति—मत की वैधता—कंपनी न्यायाधीश का आदेश—क्या उच्च न्यायालय में अपील होगी—भारतीय कंपनी अधिनियम, 1913 (1913 का 7), धाराएँ 38, 153—साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10), धारा 4(2)—लेटर्स पेटेंट, खंड 10।

कंपनी के परिसमापन के लिए किए गए एक आदेश के पश्चात, कंपनी न्यायाधीश ने भारतीय कंपनी अधिनियम, 1913 की धारा 153 के उपबंधों के तहत कार्रवाई किए जाने का एक निर्देश दिया। कंपनी के असुरक्षित लेनदारों की बैठक में, उपस्थित लेनदारों द्वारा, चाहे व्यक्तिगत रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से, संख्या में बहुमत के साथ-साथ मूल्य में तीन-चौथाई द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया था। इस बैठक में अपीलकर्ता ने, दो लेनदार कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हुए, प्रस्ताव के समर्थन में उक्त कंपनियों की ओर से अपने मत डाले। प्रस्ताव का विरोध करने वाले किसी भी लेनदार द्वारा बैठक में मतों की वैधता पर कोई आपत्ति नहीं की गई थी। जब मामला आदेश के लिए कंपनी न्यायाधीश के समक्ष आया, तो एक आपत्ति उठाई गई कि अपीलकर्ता द्वारा दो लेनदार कंपनियों की ओर से डाले गए मत वैध नहीं थे, क्योंकि अधिनियम की धारा 153(2) में यह अपेक्षित है कि लेनदारों को बैठक में व्यक्तिगत रूप से या प्रतिनिधि द्वारा उपस्थित होना चाहिए और यह कि, वर्तमान मामले में, दोनों लेनदार कंपनियां, निगम होने के कारण, बैठक में "व्यक्तिगत रूप से" उपस्थित नहीं मानी जा सकती थीं। कंपनी न्यायाधीश ने इस आधार पर आपत्ति को

खारिज कर दिया कि इसे विलंब से उठाया गया था और यह कि, किसी भी स्थिति में, मत वैध थे क्योंकि बैठक में अपीलकर्ता की उपस्थिति कंपनियों की "व्यक्तिगत रूप से" उपस्थिति के समान थी। अपील पर, पटना उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि कंपनी न्यायाधीश के आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में कोई अपील नहीं होगी बल्कि केवल उच्चतम न्यायालय में होगी और, गुण-दोष के आधार पर, उनके आदेश को अपास्त कर दिया।

अभिनिर्धारित किया गया, कि: (1) भारतीय कंपनी अधिनियम, 1913 की धारा 153(7) में "न्यायालय" शब्द का अर्थ मूल क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाला न्यायालय है, और इसलिए, कंपनी न्यायाधीश के आदेश से अपील लेटर्स पेटेंट के खंड 10 के तहत उच्च न्यायालय में होगी;

(2) यद्यपि साधारण खंड अधिनियम, 1897 के तहत, एक कंपनी एक "व्यक्ति" है ताकि जब भी किसी कानून में "व्यक्ति" शब्द का उपयोग किया जाता है, तो उसमें एक कंपनी शामिल होगी, जब तक कि कानून द्वारा कोई विशेष प्रावधान न हो, एक कंपनी जो भौतिक व्यक्ति नहीं है, किसी भी स्थान पर "व्यक्तिगत रूप से" "उपस्थित नहीं हो सकती"; और

(3) वर्तमान मामले में अपीलकर्ता द्वारा डाले गए मत विधि में मान्य नहीं थे और यह स्वीकार किए जाने पर कि यदि मत अमान्य थे, तो भारतीय कंपनी अधिनियम, 1913 की धारा 153(2) के तहत अपेक्षित मूल्य में तीन-चौथाई का आवश्यक बहुमत प्राप्त नहीं होगा और इसलिए न्यायालय द्वारा इस मामले में आगे कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती थी, आपत्ति उठाने में विलंब न्यायालय को मतों के कानूनी दोष की उपेक्षा करने का हकदार नहीं बनाएगा।

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार: सन् 1961 की दीवानी अपील सं. 201 और 202।

1957 की एल.पी.ए. सं. 13 और 14 में पटना उच्च न्यायालय के दिनांक 16 मई, 1958 के निर्णय और डिक्री से अपीलें।

अपीलकर्ताओं के लिए *ए.वी. विश्वनाथ शास्त्री, आर.के. गर्ग, एम.के. राममूर्ति, डी.पी. सिंह और एस.सी. अग्रवाल*।

भारत के लिए महान्यायवादी, *एम.सी. सेतलवाड़*।

उत्तरदातागण के लिए *बी.पी. राजगढ़िया* और *के.के. सिन्हा*।

1961 दिसम्बर 22। न्यायालय का निर्णय

दास गुप्ता, न्यायमूर्ति द्वारा प्रतिपादित —ये अपीलें उस तरीके के संबंध में एक प्रश्न उठाती हैं जिससे एक लेनदार कंपनी भारतीय कंपनी अधिनियम, 1913 की धारा 153 के उपबंधों के तहत आयोजित लेनदारों की बैठक में अपना मत मान्य रूप से डाल सकती है। यह प्रश्न गया शुगर मिल्स लि. के लेनदारों की आयोजित ऐसी बैठक के संबंध में उठता है। 14 नवंबर, 1951 को, गया शुगर मिल्स लि. के परिसमापन के लिए पटना उच्च न्यायालय में कंपनी न्यायाधीश द्वारा एक आदेश दिया गया था। 6 अक्टूबर, 1953 को, विद्वान न्यायाधीश द्वारा भारतीय कंपनी अधिनियम की धारा 153 के तहत कार्रवाई किए जाने के लिए एक आदेश दिया गया था। श्री सी. सी. बनर्जी, जिन्हें लेनदारों की बैठक आयोजित करने के लिए अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, ने डिबेंचर-धारकों, सुरक्षित लेनदारों और असुरक्षित लेनदारों की अलग-अलग बैठकें आयोजित कीं। अपने प्रतिवेदन में उन्होंने असुरक्षित लेनदारों की बैठक के संबंध में कहा कि "तीस असुरक्षित लेनदार या तो व्यक्तिगत रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित हुए और बैठक में भाग लिया", और यह कि अंततः एक लेनदार, स्टैंडर्ड वैक्यूम ऑयल कंपनी द्वारा प्रस्तावित और दूसरे लेनदार श्री के. सी. अग्रवाल द्वारा समर्थित एक प्रस्ताव "उपस्थित लेनदारों द्वारा संख्या में बहुमत के साथ-साथ मूल्य में तीन-चौथाई द्वारा" पारित किया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि इस बैठक में एक अर्जुन प्रसाद ने दो लेनदार कंपनियों, अर्थात् भंडानी ब्रदर्स और हिंदुस्तान कोल कंपनी

लि. का प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हुए, प्रस्ताव के समर्थन में इन दो कंपनियों की ओर से अपने मत डाले। प्रस्ताव का विरोध करने वाले किसी भी लेनदार द्वारा बैठक में इन मतों की वैधता पर कोई आपत्ति नहीं की गई थी और अध्यक्ष ने इस आधार पर कार्यवाही की कि ये मत मान्य रूप से डाले गए थे। यह निर्विवाद है कि यदि ये मत मान्य रूप से नहीं डाले गए होते तो मूल्य में तीन-चौथाई का आवश्यक बहुमत प्राप्त नहीं होता।

जब आवेदन न्यायालय के समक्ष अंतिम सुनवाई के लिए आया, तो उन लेनदारों की ओर से एक आपत्ति उठाई गई जिन्होंने योजना का विरोध किया था कि अर्जुन प्रसाद द्वारा दो लेनदार कंपनियों, अर्थात् भंडानी ब्रदर्स और हिंदुस्तान कोल कंपनी की ओर से डाले गए मत वैध मत नहीं थे और इसलिए लेनदारों के मूल्य में तीन-चौथाई का आवश्यक बहुमत प्राप्त नहीं किया गया था। कंपनी न्यायाधीश की यह राय थी कि इस बारे में कोई पर्याप्त स्पष्टीकरण नहीं था कि मतों की वैधता के संबंध में आपत्ति पहले क्यों नहीं उठाई गई थी और इसलिए विलंब के चरण में उठाई गई आपत्ति पर विचार नहीं किया जा सकता था। गुण-दोष के आधार पर भी उन्होंने यह निर्धारित किया कि लेनदार कंपनियों द्वारा पारित प्रस्ताव, जो अर्जुन प्रसाद को गया शुगर मिल्स लि. के असुरक्षित लेनदारों की बैठक में उपस्थित होने और कंपनियों की ओर से मतदान करने के लिए प्राधिकृत करते थे, विधि में उनकी बैठक में उपस्थिति को कंपनियों की "व्यक्तिगत रूप से" उपस्थिति और कंपनियों की ओर से उनके मतदान को कंपनियों का मान्य मतदान बनाने के लिए पर्याप्त थे। तदनुसार, उन्होंने इस आपत्ति को खारिज कर दिया।

अपील पर पटना उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने आपत्ति को स्वीकार कर लिया है, उसकी यह राय थी कि आपत्ति उठाने में विलंब न्यायालय को मतों के कानूनी दोष की उपेक्षा करने का हकदार नहीं बनाएगा और यह कि विधि में अर्जुन प्रसाद द्वारा इन दो लेनदार कंपनियों, अर्थात् भंडानी ब्रदर्स और हिंदुस्तान कोल कंपनी की ओर से डाले गए मत इन कंपनियों के मान्य मत नहीं थे। इस तर्क को कि कंपनी न्यायाधीश के आदेश के विरुद्ध

उच्च न्यायालय में कोई अपील नहीं होगी, खारिज कर दिया गया था। इसलिए, विद्वान न्यायाधीशों ने मामले के इस भाग के संबंध में कंपनी न्यायाधीश के आदेश को अपास्त कर दिया। उन्होंने, हालांकि, एक प्रमाणपत्र दिया कि मामले के मूल्य और प्रकृति के संबंध में, यह संविधान के अनुच्छेद 133(1)(ए) की आवश्यकताओं को पूरा करता है और इस न्यायालय में अपील के लिए उपयुक्त है। इसी प्रमाणपत्र पर वर्तमान अपीलें दाखिल की गई हैं।

अपीलों के समर्थन में श्री शास्त्री द्वारा हमारे समक्ष तीन बिंदु उठाए गए थे। पहला यह है कि कंपनी न्यायाधीश के निर्णय से, अपील इस न्यायालय में होगी न कि उच्च न्यायालय में। द्वितीय, यह आग्रह किया गया था कि मतों की वैधता पर आपत्ति पहले न लिए जाने के कारण आवेदन की अंतिम सुनवाई पर बहस के दौरान पहली बार उठाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। अंत में, यह आग्रह किया गया था कि मत वैध थे।

जहाँ तक प्रथम बिंदु का संबंध है, यह ध्यान दिया जाना है कि धारा 153 की उप-धारा 7, जिसे 1936 में जोड़ा गया था, यह प्रावधान करती है कि इस धारा के तहत मूल क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले न्यायालय द्वारा किए गए किसी भी आदेश से अपील न्यायालय के निर्णयों से अपील सुनने के लिए प्राधिकृत प्राधिकारी के पास होगी। इसलिए इस पर विवाद नहीं किया जा सकता था और विवाद नहीं किया गया था कि 6 अक्टूबर, 1953 को कंपनी न्यायाधीश द्वारा किए गए आदेश से अपील हुई थी। विवाद यह है कि क्या अपील इस न्यायालय में या उच्च न्यायालय में होगी। दूसरे शब्दों में, प्रश्न यह है कि, न्यायालय के निर्णयों से अपील सुनने के लिए प्राधिकृत प्राधिकारी कौन सा है? यहाँ "न्यायालय" का अर्थ मूल क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले न्यायालय के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। जब कंपनी न्यायाधीश क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हैं तो वे इसे कंपनी अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के तहत करते हैं जो कहती है कि इस अधिनियम के तहत क्षेत्राधिकार रखने वाला न्यायालय वह उच्च न्यायालय होगा जिसके पास उस स्थान पर

क्षेत्राधिकार है जहाँ कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है। जब पटना उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश मूल क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर रहे हों, तो उनके अपील योग्य निर्णयों से अपील सुनने के लिए प्राधिकृत प्राधिकारी उच्च न्यायालय के पास होगी न कि इस न्यायालय के पास। (देखें लेटर्स पेटेंट का खंड 10)। यह अनिवार्य रूप से अनुसरण करता है कि कंपनी न्यायाधीश के आदेश से अपील उच्च न्यायालय में होगी न कि इस न्यायालय में। इसलिए, अपीलकर्ता की ओर से उठाए गए प्रथम बिंदु में कोई सार नहीं है।

अगला तर्क कि आवेदन की अंतिम सुनवाई में पहली बार आपत्ति पर विचार नहीं किया जा सकता है, हमें समान रूप से दोषपूर्ण प्रतीत होता है। यह निस्संदेह सत्य है कि विरोधी लेनदार अध्यक्ष का ध्यान उस ओर आकर्षित न करने में लापरवाही के दोषी थे जिसे वे दो लेनदार कंपनियों, अर्थात् भंडानी ब्रदर्स और हिंदुस्तान कोल कंपनी की ओर से मतदान में एक दोष मानते थे, और इसे जल्द से जल्द अवसर पर न्यायालय के संज्ञान में न लाने में भी उतनी ही लापरवाही थी। हालांकि, कुछ लेनदारों की ओर से विलंब अध्यक्ष या न्यायालय को अधिनियम की आवश्यकताओं की अवज्ञा करने के लिए उचित नहीं ठहरा सकता है। यदि विधि में इन दो लेनदार कंपनियों के लिए अर्जुन प्रसाद द्वारा डाले गए दो मत मान्य रूप से नहीं डाले गए थे, तो धारा 153, उप-धारा 2 के तहत अपेक्षित बहुमत वहाँ नहीं होगा और इसलिए न्यायालय द्वारा इस मामले में धारा 153 के तहत आगे कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती थी। यदि यह सिद्ध हो जाता है कि बैठक में मान्य मतों के आधार पर अपेक्षित बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था, तो न्यायालय इस तथ्य की अनदेखी केवल इसलिए कैसे कर सकता है कि अध्यक्ष का ध्यान दोष की ओर आकर्षित नहीं किया गया था या इसे न्यायालय के संज्ञान में पहले नहीं लाया गया था? हमारी राय में, जिन विद्वान न्यायाधीशों ने अपील सुनी, वे यह सोचने में सही थे कि आपत्ति उठाने में विरोधी लेनदारों द्वारा किया गया विलंब चाहे कितना भी खेदजनक क्यों न हो, वह आपत्ति पर विचार करने से इनकार करने के लिए पर्याप्त कारण नहीं होगा।

यह हमें विवाद के मुख्य प्रश्न पर लाता है, अर्थात्, क्या दो लेनदार कंपनियों, अर्थात्, भंडानी ब्रदर्स और हिंदुस्तान कोल कंपनी द्वारा पारित प्रस्तावों ने, जो अर्जुन प्रसाद को उनकी ओर से बैठक में उपस्थित होने और वहां उनकी ओर से मतदान करने के लिए प्राधिकृत करते थे, अर्जुन प्रसाद के मतदान को मान्य मतदान बना दिया। भारतीय कंपनी अधिनियम की धारा 153(2) इन शब्दों में है:

> "यदि लेनदारों या लेनदारों के वर्ग, या सदस्यों या सदस्यों के वर्ग, जैसा भी मामला हो, के मूल्य में तीन-चौथाई का प्रतिनिधित्व करने वाला संख्या में बहुमत, जो बैठक में या तो व्यक्तिगत रूप से या प्रतिनिधि द्वारा उपस्थित हों, किसी समझौते या व्यवस्था के लिए सहमत होता है, तो वह समझौता या व्यवस्था, यदि न्यायालय द्वारा मंजूर की जाती है, तो सभी लेनदारों या लेनदारों के वर्ग पर, या सभी सदस्यों या सदस्यों के वर्ग पर, जैसा भी मामला हो, और कंपनी पर भी, या परिसमापन की प्रक्रिया से गुजर रही कंपनी के मामले में, कंपनी के समापक और अंशदाताओं पर बाध्यकारी होगी।"

सहमति उन लोगों के संख्या में बहुमत की होनी चाहिए जो बैठक में या तो व्यक्तिगत रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित हों और जो मूल्य में तीन-चौथाई का प्रतिनिधित्व करते हों। उन लोगों की सहमति जो बैठक में या तो व्यक्तिगत रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित नहीं हैं, उन्हें विचार में नहीं लिया जा सकता है। कोई भी लेनदार चाहे वह एक निगम हो या एक प्राकृतिक व्यक्ति, वह प्रतिनिधि द्वारा एक बैठक में उपस्थित हो सकता है। एक प्राकृतिक व्यक्ति निश्चित रूप से एक बैठक में "व्यक्तिगत रूप से" उपस्थित हो सकता है। क्या एक निगम एक बैठक में "व्यक्तिगत रूप से" उपस्थित हो सकता है? हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जब तक कानून द्वारा कोई विशेष प्रावधान न हो, एक कंपनी जो एक भौतिक व्यक्ति नहीं है, किसी भी स्थान पर "व्यक्तिगत रूप से" "उपस्थित"

नहीं हो सकती है। यह सत्य है कि साधारण खंड अधिनियम, 1897 के तहत, एक कंपनी एक "व्यक्ति" है, ताकि जब भी किसी कानून में "व्यक्ति" शब्द का उपयोग किया जाता है तो एक कंपनी उसके अंतर्गत शामिल होगी। हालांकि, साधारण खंड अधिनियम की परिभाषा "व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने" शब्दों की व्याख्या करने में कोई सहायता नहीं कर सकती है, और एक कंपनी के व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के मार्ग की कठिनाई को केवल वैधानिक उपबंधों या कानून का बल रखने वाले नियमों द्वारा ही दूर किया जा सकता है।

न ही अपीलकर्ता विद्वान अधिवक्ता द्वारा उद्धृत अंग्रेजी मामले '*इन री केलंतन कोको, लिमिटेड एंड रिड्यूस्ड*'[1] से कोई सहायता प्राप्त कर सकता है। उस मामले में, न्यायालय पूंजी में कमी के लिए एक याचिका पर विचार कर रहा था। यह निर्णय लेने में कि क्या कंपनी की पूंजी कम करने के लिए विशेष प्रस्ताव विधिवत पारित किया गया था, न्यायालय को यह विचार करना था कि क्या पुष्टिकरण बैठक में कोरम था, जिसमें कंपनी का एक सदस्य और कंपनी ईस्टर्न डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, लिमिटेड के एक शेयरधारक का प्रतिनिधित्व करने के लिए कंपनी समेकन अधिनियम, 1908 की धारा 68 के तहत नियुक्त एक प्रतिनिधि उपस्थित थे। एसोसिएशन के अंतर्नियमों ने प्रावधान किया था: "व्यक्तिगत रूप से उपस्थित दो सदस्य कोरम होंगे।" यह निर्धारित किया गया था कि यह विचार करते समय कि क्या कोरम था, धारा 68 के तहत नियुक्त प्रतिनिधि को गणना में लिया जाना चाहिए। धारा 68 के उपबंध भारतीय कंपनी अधिनियम, 1913 की धारा 80 के समान थे, और इसलिए एक कंपनी जो दूसरी कंपनी की सदस्य है, उस दूसरी कंपनी की किसी भी बैठक में उसके प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर सकती है। उपरोक्त मामले में ऐसे प्रतिनिधि की उपस्थिति को कंपनी के सदस्य की व्यक्तिगत उपस्थिति के समान माना गया था। यह मामला लेनदार कंपनी के प्रश्न से संबंधित नहीं है।

---

1 1920 वीकली नोट्स, भाग I, पृ. 274।

कंपनी अधिनियम, 1956 में, एक उपबंध पेश किया गया है जिसके तहत एक कंपनी जो दूसरी कंपनी की लेनदार है, अपने निदेशकों के प्रस्ताव द्वारा, ऐसे व्यक्ति को जिसे वह उचित समझे, अधिनियम के अनुसरण में आयोजित कंपनी के किसी भी लेनदारों की किसी भी बैठक में अपने प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत कर सकती है और इस प्रकार प्राधिकृत व्यक्ति कंपनी की ओर से उन्हीं अधिकारों और शक्तियों (प्रतिनिधि द्वारा मत देने के अधिकार सहित) का प्रयोग करने का हकदार होगा, (धारा 187 (1) (बी) और (2))। हालांकि ऐसा कोई उपबंध भारतीय कंपनी अधिनियम, 1913 में नहीं पाया जाना है। हमारे लिए यह विचार करना अनावश्यक है कि क्या इस नए उपबंध के तहत लेनदारों की बैठक में इस प्रकार प्राधिकृत व्यक्ति की उपस्थिति लेनदार कंपनी की "व्यक्तिगत रूप से" उपस्थिति के समान होगी। क्योंकि, वर्तमान मामला भारतीय कंपनी अधिनियम, 1913 के उपबंधों द्वारा शासित है न कि इस नए उपबंध द्वारा।

जब 1936 में कंपनी अधिनियम को संशोधित किया गया था, तो धारा 246 में एक वृद्धि की गई थी जो उच्च न्यायालय को अन्य बातों के साथ-साथ "इस अधिनियम की धारा 153 के तहत कार्यवाहियों के संबंध में लेनदारों और सदस्यों की बैठकों के आयोजन के लिए" कार्यवाही के तरीके से संबंधित नियम बनाने के लिए सशक्त बनाती है। तदनुसार, इस अतिरिक्त शक्ति के प्रयोग में पटना उच्च न्यायालय द्वारा कई नियम बनाए गए थे। नियमों का नियम 144 यह बताता है कि एक लेनदार या अंशदाता या तो व्यक्तिगत रूप से या प्रतिनिधि द्वारा मत दे सकता है। नियम 145 से 153 प्रतिनिधियों के संबंध में विभिन्न प्रश्नों से संबंधित हैं। इनमें से नियम 150 यह निर्धारित करता है कि जहाँ एक लेनदार एक निगम है वहाँ प्रतिनिधि कैसे दिया जाना है। स्वीकार्य रूप से, वर्तमान मामले में दो लेनदार कंपनियों, भंडानी ब्रदर्स और हिंदुस्तान कोल कंपनी द्वारा नियम 150 के अनुसार कोई प्रतिनिधि नहीं दिया गया था। इन नियमों में ऐसा कुछ भी नहीं है जो श्री शास्त्री के इस तर्क में सहायता कर सके कि कंपनी के निदेशकों द्वारा एक निदेशक या किसी अन्य व्यक्ति को

लेनदारों की बैठक में कंपनी का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्राधिकृत करने वाला प्रस्ताव उन्हें उस बैठक में उस कंपनी के लिए विधि में "व्यक्तिगत रूप से उपस्थित" बनाता है।

श्री शास्त्री का अंतिम तर्क यह था कि क्योंकि कंपनी के कार्य का प्रबंधन निदेशकों द्वारा किया जाना होता है और निदेशक अपनी शक्तियों में से किसी को भी अपने में से किसी एक को प्रत्यायोजित कर सकते हैं, बैठक में अर्जुन प्रसाद की उपस्थिति को उचित रूप से सभी निदेशकों की उपस्थिति और इसलिए कंपनी की "व्यक्तिगत रूप से" उपस्थिति के रूप में समझा जाना चाहिए। जैसा कि हम पहले ही संकेत दे चुके हैं, हमें यह प्रतीत नहीं होता है कि 1913 के अधिनियम में कंपनी की "व्यक्तिगत रूप से" उपस्थिति के लिए कोई उपबंध है, लेकिन उसके अलावा हम यह इंगित करना चाहते हैं कि दो कंपनियों द्वारा किया गया प्रस्ताव हमें निदेशकों की शक्तियों को अर्जुन प्रसाद को प्रत्यायोजित करता हुआ प्रतीत नहीं होता है।

उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष कि दो कंपनियों, अर्थात् भंडानी ब्रदर्स और हिंदुस्तान कोल कंपनी की ओर से अर्जुन प्रसाद द्वारा डाले गए मत मान्य मत नहीं थे, हमारी राय में, सही है।

तदनुसार अपीलें लागत के साथ खारिज की जाती हैं। सुनवाई शुल्क का एक समुच्चय।

अपील खारिज।

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यावहारिक, कार्यालयीय, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।